मोबाइल बाजार में बजेगा 'मेड इन इंडिया' का डंका

हजारों लोगों को मिलेगी नौकरी, 62,500 करोड़ होंगे खर्च

नवभारत न्यूज

नयी दिल्ली, 24 अगस्त मोबाइल फोन प्रोडक्शन को करीब 39 लाख करोड़ रुपये और एक्सपोर्ट को करीब 15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है. इससे करीब 60,000 डायरेक्ट रोजगार पैदा होने की उम्मीद है. यह स्कीम अब सिर्फ भारत में फोन की असेंबलिंग पर फोकस नहीं करेगी.

इसमें भारत में बने पार्ट्स, भारतीय आईपी, घरेलू डिजाइन, आरएंडडी और भारतीय मोबाइल ब्रांड्स को बढ़ावा दिया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, 10 से 14 महीनों में यानी 2027 के मध्य तक भारत के पहले मजबूत और भारतीय मालिकाना हक वाले स्मार्टफोन ब्रांड सामने आ सकते हैं. एपल भी भारत में आईफोन से आगे दूसरे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकता है.

बढ़ती लागत बनी चुनौती- एआई + स्मार्टफोन ने अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियों के कुछ चुनिंदा डिवाइसेस की कीमतों में बदलाव करने का ऐलान किया है. नई कीमतें तुरंत लागू होंगी. कंपनी ने यह बदलाव स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कंपोनेंट्स और इनपुट कॉस्ट में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए किया है. स्मार्टफोन इंडस्ट्री इस समय बढ़ती लागत की चुनौती से गुजर रही है.

सरकार ने MPMS स्कीम को किया नोटिफाई

श्रेणी	आंकड़ा
स्कीम की अवधि	5 वर्ष
मोबाइल उत्पादन लक्ष्य	39 लाख करोड़
पिछली PLI स्कीम का उत्पादन	20 लाख करोड़
मोबाइल एक्सपोर्ट लक्ष्य	15 लाख करोड़
पिछली PLI स्कीम का एक्सपोर्ट	7.5 लाख करोड़
मौजूदा घरेलू वैल्यू एडिशन	25-28%
मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी मे वैल्यू एडिशन	38-40%
भारत मे बने मोबाइल फोन की हिस्सेदारी	99.2%

इस तरह हैं इंसेंटिव की दरें

कैटेगरी	वर्ष	इंसेंटिव
टीएस1-बड़े निर्माता/EMS	2027-28	2.75%
टीएस1-बड़े निर्माता/EMS	2029-30	2.50%
टीएस1-बड़े निर्माता/EMS	2031	2.25%
टीएस2-भारतीय ब्रांड		5% बिक्री पर
टीएस2-भारतीय डिजाइन/R&D		अतिरिक्त 3%
घरेलू पार्ट्स/सब-असेंबली सोर्सिंग		1.5% तक अतिरिक्त

TS1 में अतिरिक्त बिक्री का लक्ष्य

वर्ष	अतिरिक्त बिक्री का लक्ष्य (करोड़ में)
2027	5,000
2028	10,000
2029	15,000
2030	20,000
2031	25,000

भारत को सुजुकी जैसी कंपनियां चाहिए

- गोयल ने सुजुकी की सफलता को बताया मिसाल
- भारत में जापानी कंपनियों की संख्या दोगुनी करने पर जोर

टोक्यो, 24 अगस्त केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को जापानी कंपनियों से भारत में अपना कारोबार और निवेश बढ़ाने की अपील की.

टोक्यो में जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जापान-भारत बिजनेस कंसल्टेटिव कमिटी और भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित गोलमेज बैठक में गोयल ने सुजुकी की भारत में चार दशक की सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में ऐसी 1,580 और सफलता की कहानियां बननी चाहिए. गोयल ने कहा कि भारत में काम कर रही जापानी कंपनियों के लिए देश की युवा कार्यबल, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाएं बड़े अवसर उपलब्ध कराती हैं. उन्होंने इस दशक में भारत में काम कर रही जापानी कंपनियों की संख्या को मौजूदा स्तर से दोगुना करने की इच्छा भी जताई.

उन्होंने सुजुकी के भारत में कारोबार को जापानी निवेश की सफल मिसाल बताते हुए अन्य कंपनियों से भी इसी तरह दीर्घकालिक और मजबूत परिचालन खड़ा करने का आग्रह किया. गोयल ने कहा कि भारत में डेटा सेंटर, विनिर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई क्षेत्रों में निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं.

गोयल 24 से 27 अगस्त तक जापान के चार दिवसीय दौरे पर हैं और उनके साथ 200 से अधिक कारोबारी प्रतिनिधियों का दल है.

> भारत और जापान के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के प्रयासों के बीच गोयल ने जापानी उद्योग जगत के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठकें कीं. इनमें ऊर्जा बदलाव, मोबिलिटी, औद्योगिक बुनियादी ढांचे, दवा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत में निवेश और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई.

मॉयल ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम सराहा

नागपुर, 24 अगस्त एक सुव्यवस्थित और पूर्ण रूप से परिभाषित वित्तीय ढांचे की स्थापना करके, यह ऐतिहासिक कानून, एम. एम. डी. आर. संशोधन अधिनियम 2026, भारत में खान और खनिज क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश सुरक्षा और निरंतर विकास के संतुलित अंशांकन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

यह संशोधन क्षेत्रीय विकास और संसाधन प्रशासन में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराता है और मजबूत करता है. धारा 9डी की शुरुआत तथा संशोधन की धारा 2 के अंतर्गत नियामक निगरानी का समुचित संरेखण, एक पारदर्शी और स्पष्ट राजकोषीय ढाँचे के साथ संतुलित समाधान प्रदान करता है. मॉयल लिमिटेड का मानना है कि यह कानून एक अनुमानित व्यावसायिक वातावरण स्थापित करता है जहां खनन संचालकों को बड़े पैमाने पर, दीर्घकालिक निवेश करने, उन्नत निष्कर्षण प्रौद्योगिकियों को उपयोग करने और खनन पट्टा क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता और सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

जेआईआईटी में वीडीएटी 2026 का शुभारंभ

- 30वीं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी पहली बार उत्तर प्रदेश में
- 441 शोधपत्रों में से 122 शोधपत्र हुए स्वीकृत

नोएडा, 24 अगस्त जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (जेआईआईटी), नोएडा में वीएलएसआई डिजाइन एंड टेस्ट (वीडीएटी 2026) की 30वीं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का गुरुवार को शुभारंभ हुआ. तीन दिवसीय यह आयोजन 20 से 22 अगस्त तक 'अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग के लिए उन्नत, बुद्धिमान, सुरक्षित और क्वांटम-रेडी सेमीकंडक्टर सिस्टम' विषय पर आयोजित किया जा रहा है.

संगोष्ठी में देश-विदेश के शिक्षाविद, शोधकर्ता, सेमीकंडक्टर उद्योग विशेषज्ञ, नीति-निर्माता, स्टार्टअप प्रतिनिधि और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं.

वीडीएटी 2026 का आयोजन जेआईआईटी ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वूमेन, एनआईटी दिल्ली और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग तथा वीएलएसआई सोसाइटी ऑफ इंडिया और आईईईई उत्तर प्रदेश सेक्शन के समर्थन से किया है. तीन दशक के इतिहास में पहली बार संगोष्ठी उत्तर प्रदेश में हो रही है.

उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिक-जी और अनुसंधान एवं विकास प्रभाग की समूह संयोजक सुनीता वर्मा मुख्य अतिथि तथा सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, मोहाली के महानिदेशक डॉ. कमलजीत सिंह विशिष्ट अतिथि रहे.

> डॉ. कमलजीत सिंह ने स्वदेशी सेमीकंडक्टर क्षमताओं को मजबूत करने के साथ अनुसंधान, डिजाइन, निर्माण और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को जोड़ने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की जरूरत बताई. डॉ. सत्या गुप्ता ने वीडीएटी के तीन दशक के सफर को रेखांकित करते हुए इसे शोधकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों और छात्रों के लिए महत्वपूर्ण मंच बताया. आयोजन के लिए 78 शोधार्थियों से कुल 441 शोधपत्र प्राप्त हुए, जिनमें 122 शोधपत्र स्वीकृत किए गए.

जेआईआईटी की निदेशक प्रो. श्वेता श्रीवास्तव, प्रो. एससी सक्सेना, वीएलएसआई सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. सत्या गुप्ता सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे.

वेकोलि 'तेजस' कार्यक्रम का सफल समापन

नागपुर, 24 अगस्त वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा युवा अधिकारियों में नेतृत्व क्षमता, नवाचार, रणनीतिक सोच एवं संगठनात्मक समझ विकसित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए 'तेजस' कार्यक्रम, के प्रथम एवं द्वितीय मॉड्यूल तथा कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन के सफलतापूर्वक संपन्न होने के पश्चात 22 अगस्त, 2026 को तेजस कार्यक्रम का सफल समापन समारोह आयोजित किया गया.

समापन समारोह में वेकोलि के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डॉ. हेमंत शरद पांडे, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री इंद्र देव नारायण तथा वेकोलि के निदेशक (वित्त एवं मानव संसाधन) श्री बिक्रम घोष प्रमुख रूप से उपस्थित थे. अपने प्रेरक संबोधन में डॉ. हेमंत शरद पांडे ने कहा कि तेजस कार्यक्रम का समापन किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि जिम्मेदार, सक्षम, साहसी एवं दूरदर्शी नेतृत्व की एक नई यात्रा की शुरुआत है. उन्होंने प्रतिभागियों से कार्यक्रम के दौरान अर्जित ज्ञान को अपने व्यवहार एवं कार्यक्षेत्र में उतारने, नवाचार को अपनाने, सत्यनिष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ नेतृत्व करने तथा संगठन में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनने का आह्वान किया.

> निदेशक (वित्त एवं मानव संसाधन) श्री बिक्रम घोष ने तेजस कार्यक्रम की उपलब्धियों की सराहना करते हुए प्रतिभागियों एवं कार्यक्रम से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी. उन्होंने तेजस की परिकल्पना, उद्देश्य एवं इसके माध्यम से प्रतिभागियों को प्राप्त हो रहे अवसरों पर अपने विचार साझा किए. कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा तैयार किए गए उत्कृष्ट विषयों में से शीर्ष तीन पेपर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए गए. तेजस कार्यक्रम में फैकल्टी तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया.

निजी ऋण में एआई का बढ़ा दखल

- डेटा विश्लेषण और निगरानी में बढ़ा इस्तेमाल
- ऋण मूल्यांकन में भी एआई की भूमिका बढ़ी

दिल्ली, 24 अगस्त. निजी ऋण क्षेत्र में निवेश और ऋण मूल्यांकन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. निजी डेट फंड सौदों की पहचान, डेटा विश्लेषण और ऋण मूल्यांकन के लिए एआई का सहारा ले रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी संख्या में निवेशक इन तकनीकों को अपनी निवेश प्रक्रिया का हिस्सा बना रहे हैं. इससे निजी ऋण बाजार में निवेश के फैसले लेने और जोखिम की निगरानी का तरीका बदल रहा है. एआई का इस्तेमाल डेटा निगरानी और हामीदारी यानी ऋण जोखिम के आकलन में किया जा रहा है.

> निजी ऋण क्षेत्र में एआई के बढ़ते इस्तेमाल के पीछे निवेश प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाने की कोशिश है. बड़ी मात्रा में उपलब्ध वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण कर एआई संभावित जोखिमों और अवसरों की पहचान में मदद कर सकता है. इससे निवेशकों को कंपनियों की वित्तीय स्थिति और ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने में सुविधा मिलती है. रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि करीब 67 फीसदी उत्तरदाता डेटा विश्लेषण और निगरानी के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं.

हवाई सफर एक साल में 32 प्रतिशत महंगा

नयी दिल्ली, 24 अगस्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही सालाना आधार पर हवाई सफर 32 प्रतिशत महंगा हुआ है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को अप्रैल-जून 2026 तिमाही के आंकड़े जारी किये. इसमें सात सेवाओं के मूल्य सूचकांक जारी किये जाते हैं. पश्चिम एशिया संकट के कारण फरवरी के बाद से विमान सेवा कंपनियों ने हवाई किराये में बढ़ोतरी की थी. इसका सीधा असर हवाई सेवा मूल्य सूचकांक पर दिख रहा है. इस सूचकांक में सबसे बड़ा घटक हवाई किराया ही है.

क्रूड सस्ता, ईरान से खतरा बरकरार

अमेरिकी प्रतिबंधों की आहट से तेल बाजार में बढ़ी चिंता

नई दिल्ली, 24 अगस्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में सोमवार को 1 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण तेल बाजार की चिंता कम नहीं हुई है.

निवेशकों ने अमेरिका की ओर से ईरान पर नए प्रतिबंधों के संभावित ऐलान से पहले मुनाफावसूली की, जिसके चलते ब्रेंट क्रूड 1.22 डॉलर यानी 1.29 प्रतिशत गिरकर 93.17 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.20 डॉलर यानी 1.38 प्रतिशत टूटकर 85.86 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इससे पहले पिछले सप्ताह दोनों बेंचमार्क में 5 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई थी. अमेरिका ईरान पर अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने प्रतिबंधों को लेकर संकेत दिए हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों को भी चेतावनी दी है. दूसरी ओर ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध किया है.

योगी को फ्री हैंड, खुद बांटेंगे टिकट

2024 में मिली हार के बाद पार्टी का फैसला

लखनऊ, 24 अगस्त. लोकसभा चुनावों में मिली हार से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक अहम फैसला लिया है. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दे दिया है. 2027 विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सीधे अब योगी के हाथों में होगी.

सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में इसका दावा किया जा रहा है. लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा चुनाव के लिए अब तक भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ही उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी फैसला लेता था. हालांकि, एनडीए के सहयोगी दलों अपना दल (एस) आरएलडी, निषाद पार्टी और सुभासपा के साथ सीटों के बंटरवारे का फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा.

सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के सीएम योगी से अच्छे संबंध माने जाते हैं. विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री से बेहतर तालमेल के लिए ही उन्हें यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक लिस्ट सौंपी थी. इस लिस्ट में 24 से ज्यादा सांसदों के टिकट काटकर नए उम्मीदवारों को टिकट देने की बात कही गई थी. हालांकि, केंद्रीय नेतृत्व ने इसे मानने से इनकार कर दिया था. भाजपा ने 64 में से 47 सांसदों को दोबारा उम्मीदवार बनाया, लेकिन 47 में से 26 सांसद चुनाव हार हार गए. उत्तर प्रदेश में भाजपा केवल 33 सीटों पर सिमट गई. जिसका नतीजा यह हुआ कि केंद्र में पार्टी को अपने दम पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका.

बागियों को रोकने के लिए खास प्लान

बीजेपी की शुरुआती इंटर्नल सर्वे रिपोर्ट में पार्टी को 190 से 205 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. हालिया राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी को डर है कि अगर ज्यादा विधायकों के टिकट एक साथ काटे गए, तो वे सपा, कांग्रेस या बसपा में जा सकते हैं. जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है. इस बगावत को रोकने के लिए पार्टी ने सीट बदलने की रणनीति बनाई है. सूत्रों के मुताबिक, जिन विधायकों के खिलाफ जनता की नाराजगी है, लेकिन उनका सियासी नुकसान ज्यादा हो सकता है, उन्हें किस अन्य सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ाया जा सकता है. जबकि, कमजरो और गैर-प्रभावशाली विधायकों के टिकट काटे जाएंगे.

क्यों पंजाब की राजनीति में कमजोर हैं प्रवासी

33 लाख की आबादी के बाद भी नहीं डालते असर

चंडीगढ़, 24 अगस्त. पंजाब की एक बड़ी आबादी भले ही कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में बसी है या जाने का सपना देखती है, लेकिन भारत के ही कई राज्यों के लोग वहां बसे हुए हैं. ऐसे करीब 33 लाख लोग यूपी, बिहार समेत कई राज्यों से हैं, जिनका पंजाब दूसरा घर जैसा है. ये लोग पंजाब में रोजी-रोटी कमाते हैं.

कुछ लोग कमाकर लौटते हैं तो कुछ लोगों ने पंजाब में ही घर-मकान बना रखे हैं. दशकों से ये लोग पंजाब में हैं, फिर भी सूबे की राजनीति में उनका दखल न के समान है. पंजाब के चुनाव में प्रवासी कामगार या फिर अन्य लोग यहां मुद्दा नहीं बनते. 33 लाख लोग आखिर पंजाब की राजनीति में क्यों इतने कमजोर हैं, यह सोचने वाली बात है.

फसलों की बुआई और कटाई के समय में बड़ी संख्या में पूर्वी यूपी और बिहार के लोग पंजाब पहुंचते हैं. फसली सीजन के बाद ये लोग लौटते हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं, जो जालंधर, लुधियाना समेत कई शहरों के उद्योगों में काम करते हैं. पंजाब में 1971 में 4,000 प्रवासी ही थे, जो अब 33 लाख हो चुके हैं. इनमें से 70 फीसदी लोग उद्योगों में काम करते हैं, जबकि 30 पर्सेंट लोग ऐसे हैं, जो खेती के कामों में हैं.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब की कुल आबादी में प्रवासियों की हिस्सेदारी 15 फीसदी तक है. इसके अलावा इनमें से 80 से 90 फीसदी यूपी और बिहार के हैं.

पंजाब में जिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रवासियों की अच्छी-खासी आबादी है. उनमें लुधियाना साउथ, लुधियाना ईस्ट, लुधियाना सेंट्रल, आतम नगर, साहनेवाल, जालंधर सेंट्रल, जालंधर नॉर्थ, जालंधर वेस्ट, फगवाड़ा, आदि शामिल हैं. इसके अलावा फतेहगढ़ जिले में भी इनकी अच्छी आबादी है. पर अहम सवाल यह है कि इतनी आबादी और कई विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे बदलने का दम रखने के बाद भी पंजाब की राजनीति में इन प्रवासी वोटरों की चर्चा क्यों नहीं होती.

> **एकमात्र बिहारी, जो बने थे पंजाब में विधायक**
> बिहार के इकलौते व्यक्ति कुंवर विजय प्रताप सिंह थे, जो पंजाब काडर के आईपीएस थे. वह अमृतसर नॉर्थ सीट से आप से विधायक चुने गए थे. वह मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं. पंजाब में वह पुलिस में कई अहम पदों पर रहे थे. इससे पहले बसपा ने एक सीट नवांशहर की 2022 में जीती थी.

कई राज्यों में राज्यपाल बदले जाएंगे

नई दिल्ली, 24 अगस्त. केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल से पहले राजभवनों में, जिनको आजकल लोकभवन कहा जाने लगा है, बदलाव की चर्चा है. इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो सकती है. उत्तर प्रदेश में पिछले छह साल से आनंदी बेन पटेल राज्यपाल हैं.

चुनाव से पहले उनको हटाए जाने की खबर आ रही है. इस बीच वे 10 दिन की लंबी छुट्टी पर चली गई हैं. कई जानकार यह भी कह रहे हैं कि वे अब शायद ही लोकभवन में लौटें. हालांकि उनके बारे में कोई पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता है. मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी उनको समाप्त मान लिया गया था.

बहरहाल, पिछले दिनों उन्होंने योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में जाकर वहां की जैसी दुर्दशा बताई थी उससे भी अंदाजा लग रहा था कि उनके दिन यूपी में पूरे हो गए हैं.

कहा जा रहा है कि भाजपा के किसी ब्राह्मण नेता को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया जा सकता है. कर्नाटक में भी राज्यपाल थावरचंद गहलोत को बदले जाने की चर्चा है. वहां विधानसभा चुनाव में दो साल से कम समय रह गया है.

किसी तेजतर्रार नेता को राज्यपाल बना कर भेजे जाने की खबर है. इसके अलावा तमिलनाडु में भी नया राज्यपाल भेजे जाने की चर्चा है. आरएन रवि को वहां से कोलकाता भेजे जाने के बाद केरलम के राज्यपाल तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं. मध्य प्रदेश में भी नया राज्यपाल भेजे जाने की चर्चा है. जानकार सूत्रों का कहना है कि भाजपा के संसदीय बोर्ड में बदलाव होने वाला है उसके दो या तीन सदस्य राज्यपाल बनाए जाएंगे.

फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड
Fusion Finance
पंजीकृत कार्यालय का पता: एच-1, सी ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर, नारायणा विहार, नई दिल्ली - 110028, भारत। **कॉर्पोरेट कार्यालय:** प्लॉट संख्या 86, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर 32, गुरुग्राम, हरियाणा - 122001, भारत।
CIN: L65100DL1994PLC061287 | **वेबसाइट:** www.fusionfin.com

सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि आम जनता और हमारे सम्मानित ग्राहकों की सुविधा के लिए, नीचे उल्लिखित फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड की **बंगाली स्क्वायर एमएफआई शाखा** को **दिनांक 25/11/2026** से स्थायी रूप से स्थानांतरित की जाएगी। **दिनांक 26/11/2026** से **बंगाली स्क्वायर एमएफआई शाखा** के सभी ग्राहकों को **विजय नगर एमएफआई शाखा** द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ग्राहकों से अनुरोध है कि नीचे उल्लिखित तिथि से वैकल्पिक शाखा में सेवाओं का लाभ उठाएं।

1. बंद की जाने वाली शाखा का नाम एवं पता:	मेसर्स फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड, सी/ओ श्री जितेंद्र सिंह देवड़ा एवं सोहन सिंह देवड़ा, निवासी मकान नं. 374, आलोक नगर, वार्ड नं. 41, जोन-19, कर्नाटक स्कूल के सामने, कनाड़िया मेन रोड, बंगाली स्क्वायर, इंदौर, मध्य प्रदेश - पिन-452016
2. वैकल्पिक शाखा का नाम एवं पता (पोर्टफोलियो हस्तांतरित):	मेसर्स फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड, सी/ओ श्रीमती किरण निगम, निवासी मकान नं. 1054, स्कीम नं. 114, पार्ट 01, विजयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश - पिन-452010
स्थानांतरण की तिथि	25-11-2026

हम अपने ग्राहकों को आश्वस्त करते हैं कि कंपनी इस प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को किसी भी प्रकार की असुविधा या सेवा में व्यवधान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरत रही है। **बंगाली स्क्वायर एमएफआई शाखा** के सभी संबंधित ग्राहकों के मौजूदा एमएफआई ऋण खातों को सुचारु रूप से **विजय नगर एमएफआई शाखा** में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मौजूदा समझौतों के नियमों और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी स्पष्टीकरण या सहायता के लिए ग्राहक शाखा प्रबंधक या कंपनी से निम्नलिखित माध्यमों पर संपर्क कर सकते हैं: **टोल-फ्री नंबर (प्रातः 7:00 बजे - रात्रि 8:00 बजे): 18001037808 | ई-मेल आईडी: customercare@fusionfin.com**

स्थान: मध्य प्रदेश, दिनांक: 25/08/2026 **फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड के लिए, हस्ता./-, अधिकृत अधिकारी**

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय : ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र - 400072
रतलाम शाखा: तल मंजिल, 19, पैलेस रोड, चिंतामन गणेश मंदिर के सामने, रतलाम - 457001 (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 02210001211 / रतलाम शाखा) हयात खा (ऋणी) नसरीन बी (सह-ऋणी)	संपूर्ण संपत्ति का वह भाग एवं समस्त अंश, सर्वे नंबर 19/4/1, ग्राम हापुखेड़ी, तहसील रतलाम, जिला रतलाम, भाटपचलाना रोड, प्लॉट नंबर 49 (दक्षिणी भाग), हापुखेड़ी, रतलाम, म.प्र. 457001, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः सड़क, पश्चिमः उक्त सर्वे नंबर की शेष भूमि, उत्तरः उक्त प्लॉट नं. 49 के शेष भाग पर बना मकान, दक्षिणः उक्त सर्वे नंबर की शेष भूमि	09-06-2026 & ₹ 15,87,685/-	21-08-2026
2	(लोन कोड नं. 02210001300 / रतलाम शाखा) महेश राठौर (ऋणी) ममता राठौर (सह-ऋणी)	संपूर्ण संपत्ति का वह भाग एवं समस्त अंश, जीएफ एफएफ मोहल्ला काटजू नगर, स्कीम नंबर 44, काटजू नगर रोड, वार्ड नंबर 14, प्लॉट नंबर 186 का दक्षिणी भाग, रतलाम, मध्य प्रदेश 457001. **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः गली, पश्चिमः सड़क, उत्तरः भोला राम का मकान, दक्षिणः ओपन भूमि	09-06-2026 & ₹ 21,73,884/-	21-08-2026

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 25.08.2026
प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड